P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-1* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 की संभावनाएं एवं चुनौतियां

भावना तिवारी
शोधार्थी,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
जे. एस. विश्वविद्यालय,
शिकोहाबाद, उत्तर प्रदेश
भारत

सारांश

शिक्षा राष्ट्रीय एवं विकास का आधार है, शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज राष्ट्र, एवं स्वयं का विकास कर सकता है, शिक्षा एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। यह एक ऐसा प्रेरक साधन है जिससे देश के पढ़ने वाले बच्चों और युवाओं का भविष्य की दिशा एवं दशा तय करेगा । भारत की एक लाख से अधिक जनसंख्या का लगभग आधी आबादी युवाओं की है। युवाओं को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,नवाचार और अनुसंधान सम्बधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एवं नये नये शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी।

नई नीति 2019 के प्रारूप में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता तथा साथ ही त्रि–भाषा सूत्र को प्राथमिकता के साथ रखा गया है जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में पहले से विद्यमान है। इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता शिक्षा के अधिकार आदि, के दायरे का व्यापक रूप से क्रियान्वित करना हो। इस शिक्षानीति में शिक्षा की जो संरचनात्मक ढ़ाचा है दसे 5+3+4 के फार्मूले के तहत चार चरणों में वर्गीकृत किया जायेगा।

मुख्य शब्द : राष्ट्रीय , शिक्षा , नीति, संभावनाऐं, चुनौतियां।

प्रस्तावना

नई शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप तैयार करने के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरीरंमन की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी समिति ने अपनी प्रमुख सिफारिशों में आर0टी0ई0 के दायरें को बढ़ाने की बात कही तथा स्नातक स्तर के जो पाटयक्रम है उनको भी संशोधित किया गया एम0फिल0 प्रोग्राम को रद्द करने की भी सिफारिश की गयी है नवीन पाठ्क्रम को 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिए 5+3+3+4 शिक्षा का श्रृंखलाबद्ध ढांचा तैयार किया गया है । समिति ने अपनी सिफारिश में निजी स्कूलों को 25% आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश में मनमानी भ समीक्षा किया जाना सुनिश्चित है। नई शिक्षा नीति ने निजी स्कूलों को एवं सौगात देकर कि वे अपनी फीस निर्धरित करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन ने मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि नही कर सकेगें। इसबात पर जरा दिया गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थ्ज्ञापना हो जो सतत् मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा के विकास कार्यान्वयन ,मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का एकमात्र उददेश्य एक ऐसा शिक्षा नीति तैयार करना जो छात्रों का सर्वागीण विकास कर सके उनके अन्दर कौशल विकसित कर सके तथा सम्पूर्ण ज्ञान से लैश कर सकें।

शिक्षा से जुड़ी समस्याएँ

प्राथमिक शिक्षा की समस्या

शिक्षा की गुणवत्ता में कमी

आग के समय में सभी युवक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते है । चाहे वे शिक्षक बनने का ठप्पा लग जाने के बाद शिक्षक अपने मूलउद्देश्य पढ़ना पढ़ाने से भटक जाते है। जिनका प्रभाव विद्यालय में पढ़ने चाले छात्रों पर पड़ता है और इसका दुष्परिणाम देख जाता हे कि छात्र विद्यालय आना छोड़ देते है। क्योंकि अभिभावक भी यह आकलन कर लेते है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ायी नहीं होती है। शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं आतें है और कुछ शिक्षक जो विद्यालय आते भी है उनके उपर इतना बोझ होता है कि वे अपना ध्यान बच्चों को पढ़ाने में नही दे पाते ।

विद्यालयों की कमी

भारत में लगभग 6 लाख विद्यालयों मे कक्षा–कक्ष की कमी है उनके बैठने एवं अध्ययन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है।

शिक्षकों की कमी

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 35 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस लक्ष्य को अभी हासिल नहीं किया जा सका है शिक्षको की कमी के कारण एक शिक्षक पर कई कक्षाओं का भार होता है। अतः इस परिस्थिति में शिक्षक सिर्फ खानापूर्ति करने तक ही सीमित रह पाता है। उसके द्वारा पठन–पाठन करा पाना सम्भव नही है।

बुनियादी ढांचे में कमी

बिजली, पानी, शौचालय, पुस्ताकलय कक्ष ,कम्प्यूटर कक्ष आदि अनेक सुविधाओं से विद्यालय वंचित है इसलिए सभी अभिभावको का रूझान निजी विद्यालयों की तरफ है चाहे वहाँ गुणवत्तापरक शिक्षा का आभाव ही हो लेकिन विद्यालयों का बाह्य आकर्षण अभिभावकों को आकर्षित करता है छात्र भी उसी विद्यालय में पढ़ना चाहते है जहां आधुनिक सुख सुविधाऐं प्राप्त हो सरकारी स्कूलो में करीब 90 प्रतिशत धन अध्यापको के वेतन पर खर्च करना पड़ रहा है। जिसका आउट पुट नगण्य दिखायी पड़ रहा है।

गरीबी

मिड डे मिल और मुफ्त शिक्षा के वावजूद भी करीब 30 प्रतिशत छात्र बिना पूर्वप्राथमिक शिक्षा पूरा किये बिना ..... छोड़ दे है। इससे सरकार को अपव्यय की समस्या से जूझना पड़ रहा है ।

माध्यमिक शिक्षा की समस्या

मध्यामिक स्तर पर जो शिक्षा व्यवस्था विद्यमान है उसमे सरकारी विद्यालयों मे शिक्षकों की कमी , संसाधनों का आभाव, जो शिक्षक कार्य भी कर रहें है । अधिकांश संविदा पर है और उनके आधे से अधिक अप्रशिक्षित है केवल 60 प्रतिशत बच्चे ही आगे की पढ़ायी जारी रखना चाहतें है अर्थिक मजदूरी या पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण अधिकांश छात्र साधरण रोजगार में लग जाते है।

शोध अध्ययन से प्राप्त हुआ है कि छात्रों पर पढ़ाई इतना दबाव है कि छात्र सफलता न प्राप्त करने अथवा अच्छे अंक न लाने की स्थिति में आत्महत्या तक करने लगें।

उच्च शिक्षा की समस्याऐं

MHRD ने 2017 में अपनी रिर्पोट में भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति एवं चुनौतियाँ और समस्याएं पर अपनी रिर्पोट दी थी शिक्षकों की कमी –UGC के मुताबित कुल स्वीकृत शिक्षक पदों में से संसाधनों की कमी –सरकार की बजट का अधिकांश हिस्सा केन्द्रित विश्वविद्यालयों और उनके कालेजो द्वारा उपयोग किया जाता हैं। जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबध कालेजो को अनुदानित राशि देने भर का बजट नहीं होता है। जिसका असर छात्रों की पठन–पाठन और उनके लिए संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता है।

भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत ही कमी है आज भरत का कोई विश्वविद्यालय विश्व के Top 100 में अपना स्थान नहीं बना सका संस्थानों का नैक द्वारा एक्रेशन कराना अनिवार्य है लेकिन अभी तक अधिकांश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय नैक द्वारा एक्रेशन नहीं है।

शिक्षकों की जवाब दे ही सुनिश्चित नहीं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पढ़ानें वाले प्राफेसर की कोई जवाब देही निर्धारित नहीं है अगर परिणम खराब है तो उसकी जिम्मेदारी निश्चित की जाय शिक्षकों के पढ़ाने के अतिरिक्त उन्य कार्य से वंचित रखा जाय प्रायः देखने को मिलता है प्रोफेसर विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक कार्यो में लिप्त रहतें और मूलकार्य से विमुख होते है जिसका प्रभाव छात्रों के परिणाम पर दिखायी पड़ता है। उनका समय से कभी पाठ्क्रम नहीं पूरा हो पाता है।

शिक्षा की वास्तविक स्थिति

एक आंकड़े से पता चलता है कि 12 से 24 वर्ष के मात्र 12.4 प्रतिशत छात्र ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा रहें है। शिक्षक छात्रों को पढ़ने के लिए आकर्षित करने में विफल रहें है । शिक्षा तंत्र भी तमाम विभागों की तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारत का जो शोध है यह निम्न स्तर का है ज्यादातर छात्र जो शोधार्थी है वे मूल शोध करने की बजाय दूसरे की नकल कर ही अपना शोध पूरा कर लेते है अर्थात यहाँ मौलिक शोध बहुत कम है हमारे विश्वविद्यालय आज राजनीति में सक्रिय हो जाता है कुलपतियों तक नियुक्ति में राजनीति आधार पर ही होता है भारत में शिक्षा चाहे वह माध्यमिक हो या उच्चशिक्षा अथवा शोध ही क्यों न हो उसके रास्ते में बड़ी बाधा धन की कमी है । फिर भी सरकार प्रयास कर नहीं है अनुदान अथवा छात्रवृतियां देकर इसको दूर करने में .....

मुख्य सिफारिशें

1. शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना –
2. नये पाठ्क्रम और शिक्षण पद्धति में उचित बदलाव।
3. शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन।
4. शिक्षकों की नियुक्ति में उच्च शिक्षित प्रशिक्षित जिज्ञासु शिक्षकों से समृद्ध बनाना । 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता चार वर्षीय बी0एड0 डिग्री होगी।
5. शिक्षक पात्रता परीक्षा में सुधार किया जायेगा जिससे बेहतर शिक्षकों की तलाश पूरा हो सकें ।
6. समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना जहां बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर मिलें।
7. स्कूलों के रेगुलेशन के लिए स्वतंत्र राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।
8. उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार हेतु विविध विषयों पर आधारित उच्च शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण ।
9. छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए सृजनात्मकता पर विशेष बल ।
10. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास के लिए आयोग की पुर्नसंरचना।
11. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जायेगा।
12. वोकेशनल शिक्षा सभी स्कूल और उच्च शिक्षा का अभिन्न हिस्सा होगा।

13. पुस्ताकालय को जीवंत बनाने व गतिविधियों को कराने पर बल।

नई शिक्षा नीति 2019 से पहले शिक्षा में सुधार के लिए अनेक समितियों एवं आयोग का गठन किया जा चुका था सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में राधाकृष्णन आयोग (विश्वविद्यालय शिक्षा) आयोग 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964 में शिक्षा आयोग 1968 शिक्षा नीति (कोठारी आयोग के सुझावों परान्त) का प्रस्ताव , 1936 में नयी राट्रीय शिक्षा नीति ,199 में राममूर्ति समिति. 1993 यशपाल समिति 2017 नयी शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए के 0 कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया ।

लेकिन आज भी शिक्षा के गुणात्मक स्तर को प्राप्त नहीं कर पायें है। उन कमियों को जानने का और उसे दूर करने का पुनः प्रयास किया जा रहा है। उसी का परिणाम है नई शिक्षा नीति 2019 का प्रार्दुभाव।

नई शिक्षा नीति की प्रमुख चुनौतियाँ

शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत वित्तीय एवं प्रशांसनिक उपायो के द्वारा राज्यो एवं केन्द्र सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों को बॉटने की आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत सभी स्तरो पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखना एवं देश की शैक्षिक जरूरतों का आकलन एवं रख रखाव शामिल है।

देश के समक्ष शिक्षा से सम्बधित निम्नलिखित चुनौतियाँ है।

1. देश में योग्य शिक्षको की कमी है। क्योंकि अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षक के पेशे में वही लोग आते है जो हर जगह से असफल होते है अन्तः में परिस्थिति वश शिक्षक के पेशे में सम्मिलित होते है लेकिन उनके अन्दर रूचि का पूर्णतयः आभाव दिखायी पड़ता है अतः आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक के पेशे में उन लोगो को आकर्षित किया जाय जो योग्य हो ,ज्ञानवान हो उनके अन्दर नैतिकता की भावना से ओतप्रोत हो।
2. शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा से सम्बन्धित जितने भी आयोग एवं समितियो का गठन किया गया सबने अपनी रिर्पोट में शिक्षक –प्रशिक्षण एवं संस्थाओं में गुणवत्ता की कमी एक प्रमुख समस्या के रूप में बतलाया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों का दायित्व बनता है कि इनका समय–समय पर आकलन कर उनके ऊपर अंकुश लगा सकते है लेकिन अन्य विभागों की भाँति शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार का बोल बाला है। जिससे यहाँ भी सुधार नहीं हो पा रहा है। शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं गुणात्मक रूप से बढ़ रही है लेकिन गुणवत्ता में ह्रास दिनों –दिन बढ़ता चला जा रहा है। अतः इस पर भी केन्द्र एवं राज्य सरकारे मिल जुलकर कोई ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय जो है ।
3. माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण भी एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिक्षा देकर अध्ययनरत युवक युवतियों को रोजगार की समस्या से निजात मिल सके। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सशक्तिकरण से 2022 तक 50 करोड़ कुशल कर्मियों के रष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी ।
4. स्कूली शिक्षा में सुधार करने के लिए शिक्षण विधियों प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में सुधार करने की जरूरत है।
5. शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने शिक्षक में नवाचारी पद्धतियों का विकास करने सहित उन्हें व्यवहारिक स्वरू‍प में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए।
6. दोष पूर्ण मूल्यांकन प्रणाली भी एक प्रमुख चुनौती है इसको भी दूर करने की जरूरत है ।
7. बच्चे की अस्मिता के प्रति शिक्षक का नजरिया यदि विद्यालय का वातावरण बच्चे के लिए असहज ,असुरक्षित , अपमानित, हीनता भाव पैदा करने वाला हो तो बच्चे हर परिस्थिति में पिछड़ने लगते है और एक समय आता है जब वे विद्यालय छोड़ देते है उनका नामाकंन एवं ठहराव भी एक प्रमुख चुनौती है।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार जन सहयोग के माध्यम से सामने रखे है। उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसका भी एक प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से किया गया है] नीति के कार्यावन्यन की प्रगति और समय–समय पर उभरती हुई चुनौतियों और सम्भावनाओं पर ध्यान दिया जायेगा । मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रयास निःसंदेह ही प्रशंसनीय है जिसने शिक्षा के नवीन पहलुओं पर अपना ध्यान और लोगो का ध्यान आकर्षित कर शिक्षा को एक चुनोती के रूप में लिया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

एंसाइक्लोपिडिया ऑफ एजुकेशन रिर्सच द्वारा प्रोसेसिंग इअर बुक।

शिक्षा सामाजिकी संक्षिप्त (1948 से अब तक)।

भारत में शिक्षा अनुसंधान सर्वेक्षणः एम0बी0 बुश ।

सिंहल,महेशचन्द्र : भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ,राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी,जयपुर। (1991)

गुप्ता, एस. पी.: भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं शारदा प्रशासन, इलाहाबाद।

www.NCERT. NIC.in